Toppersnotes®
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

भाग – 5

भारतीय अर्थशास्त्र एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

RAS

भाग-5

भारतीय अर्थशास्त्र एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था

S.No.	Chapter Name	Page No.

1.	**राष्ट्रीय आय**
	• राष्ट्रीय आय के पहलू
	  ○ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)
	  ○ सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए तरीके:
	• शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)
	• सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)
	• शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)
	• राष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीके
		1

2.	**लोक वित्त**
	• सब्सिडी
	  ○ कृषि सब्सिडी की आवश्यकता
	  ○ सब्सिडी का वर्गीकरण
	  ○ कृषि सब्सिडी के लाभ और मुद्दे
	• संवितरण के विभिन्न तरीके
		7

3.	**बजट निर्माण**
	• वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
	  ○ बजट के प्रकार
	  ○ बजट घटक
	  ○ प्राप्तियां
	  ○ व्यय
	  ○ विकासात्मक और गैर-विकासात्मक व्यय
	  ○ योजनागत और गैर-योजनागत व्यय
	  ○ बजट में अनुमान
	  ○ बजट के अधिनियमन की प्रक्रिया
	• सरकारी खाते
	• घाटा वित्तपोषण
	  ○ घाटे के वित्तपोषण की आवश्यकता
	  ○ घाटे के वित्तपोषण के साधन
		11

4.	**भारत में कर सुधार**
	• कराधान
	  ○ कराधान के पीछे उद्देश्य
	  ○ कराधान के तरीके
	• कर के प्रकार
	  ○ प्रत्यक्ष कर
	  ○ अप्रत्यक्ष कर
	• कर सुधार
	  ○ भारत के कर सुधारों का परिचय
	  ○ आंकड़े
	  ○ भारत के कम कर-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के कारण
		17

	○ निम्न टैक्स-टू-जीडीपी अनुपात के निहितार्थ ○ प्रत्यक्ष कर सुधार • विभिन्न समितियां ○ राजा चेलिया समिति (1990 के दशक के प्रारंभ में) ○ विजय केलकर समिति (2002) ○ ईश्वर पैनल 2015 ○ आयकर सुधारों पर अरबिंद मोदी समिति • लाफ़र वक्र	
5.	**मुद्रास्फीति** • मुद्रास्फीति के कारण ○ अन्य कारक • मुद्रास्फीति के प्रकार • मुख्य मुद्रास्फीति बनाम शीर्षक मुद्रास्फीति ○ मुद्रास्फीति की जांच के उपाय • WPI बनाम CPI • उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) • आवास मूल्य सूचकांक • सेवा मूल्य सूचकांक (SPI) • मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ○ मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा • सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीतिकारक/जीडीपी डिफ्लेटर ○ आधार प्रभाव (Base Effect) ○ अन्य महत्वपूर्ण शर्तें	**30**
6.	**भारत में बैंकिंग** • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ○ भारतीय रिजर्व बैंक की आय और व्यय के स्रोत ○ भारतीय रिजर्व बैंक के भंडार और अधिशेष पूंजी ○ भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति और देनदारियां • भारत में बैंकों का विभाजन ○ अनुसूचित बैंक • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ○ उद्देश्य • सहकारी बैंक • गैर अनुसूचित बैंक • विशिष्ट बैंक ○ विभेदित बैंक ○ विकास बैंक • गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) ○ NBFC के रूप में पंजीकरण करने की शर्तें ○ बैंकिंग क्षेत्र में सुधार • बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का प्रस्ताव रखने वाली समितियां ○ नरसिम्हम समिति- I (1991) ○ नरसिम्हम समिति-द्वितीय (1998) ○ नचिकेत मोर समिति (2013) ○ पीजे नायक समिति (2014) ○ बेसल मानदंड • पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (CRAR) • गैर निष्पादित परिसंपत्ति / नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) और दबव्रस्त परिसंपत्ति ○ ऋणों का वर्गीकरण ○ NPA समाधान के उपाय • दिवाला और दिवालियापन	**39**

	○ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ○ इरादतन डिफ़ॉल्टर्स ○ कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष • वित्तीय समावेशन ○ वित्तीय समावेशन की आवश्यकता ○ सरकारी उपाय	
7.	**मुद्रा** • मुद्रा का विकास • मुद्रा के कार्य • मुद्रा का वर्गीकरण ○ पूर्ण मुद्रा ○ पूर्ण मुद्रा प्रतिनिधि ○ साख मुद्रा ○ मुद्रा के प्रकार • क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन • मुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक समुच्चय ○ मुद्रा बाजार ○ भारत में मुद्रा बाजार के घटक ○ संगठित क्षेत्र ○ असंगठित क्षेत्र ○ मुद्रा आपूर्ति ○ मुद्रा गुणक • मौद्रिक समुच्चय • वित्तीय प्रणाली	**59**
8.	**मौद्रिक नीति** • मात्रात्मक उपकरण • खुला बाजार संचालन ○ OMO का लक्ष्य ○ बाज़ार स्थिरीकरण योजना ○ गुणात्मक उपकरण • मौद्रिक नीति समिति ○ उर्जित पटेल समिति	**68**
9.	**स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट** • शेयर बाजार ○ कार्य ○ राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज ○ स्टॉक एक्सचेंजों में खिलाड़ी • भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) ○ उत्पाद व्यवसाय • स्पॉट एक्सचेंज ○ स्पॉट एक्सचेंज के लाभ • शेयर बाजार की महत्वपूर्ण शर्तें	**74**
10.	**आर्थिक संवृद्धि एवं विकास** • आर्थिक संवृद्धि • आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक • आर्थिक कारक ○ गैर-आर्थिक कारक ○ आर्थिक विकास ○ आर्थिक संवृद्धि और विकास के बीच अंतर • असमानता	**81**

	○ असमानता का वर्गीकरण • सांख्यिकी ○ विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार ○ आय में असमानता के कारण ○ आय असमानता के परिणाम ○ भविष्य के पहलू • लिंग असमानता सूचकांक • खुशहाली ○ विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2021 • नज और सार्वजनिक नीति ○ समावेशी वृद्धि और संबंधित मुद्दे ○ समावेशी वृद्धि की विशेषताएं ○ भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता • भारत में निर्धनता आकलन • जनसांख्यिकीय विभाजन ○ भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश ○ भारत में श्रम कानून ○ सतत विकास लक्ष्य (SDGs) • सतत विकास के तत्व	
11.	**अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र** • भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक • अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर से टरशियरी सेक्टर की तरफ का क्रमिक विकास • विभिन्न क्षेत्रकों की पारस्परिक निर्भरता • भारत में विभिन्न सेक्टर का विकास और वर्तमान स्थिति ○ भारत के जीडीपी में अलग अलग सेक्टर का योगदान ○ भारत के अलग अलग सेक्टर में रोजगार के अवसर • अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गीकरण ○ संगठित क्षेत्र ○ असंगठित क्षेत्र ○ सार्वजनिक क्षेत्र ○ प्राइवेट क्षेत्र	**95**
12.	**गरीबी एवं बेरोज़गारी** • गरीबी ○ गरीबी के प्रकार • लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक • भारत में गरीबी का आकलन ○ गरीबी रेखा • गरीबी के आकलन के लिए विभिन्न समितियों की अनुशंसाएं • रंगराजन समिति • भारत में गरीबी के कारण • गरीबी का जाल • भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम • बहुआयामी निर्धनता सूचकांक • बेरोजगारी ○ भारत में बेरोजगारी का उपाय ○ भारत में बेरोज़गारी के प्रकार ○ भारत की आर्थिक वृद्धि से देश में रोजगार क्यों नहीं बढ़ा? • भारत में बेरोज़गारी के कारण ○ बेरोज़गारी का प्रभाव • सरकार की पहल ○ जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	**99**

	○ ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (TRYSEM) ○ ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ○ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ○ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ○ काम के बदले भोजन कार्यक्रम ○ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)	
13.	**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता** • कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का औचित्य • समाज के कमजोर वर्ग • बच्चों से जुड़े मुद्दे • अनुसूचित जनजाति/SC/OBC • युवा के बारे में • वरिष्ठ नागरिक • विकलांग व्यक्ति • अल्पसंख्यक • LGBT समुदाय	**111**
14.	**भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के रुझान** • विदेशी पूंजी ○ विदेशी पूंजी की आवश्यकता • विदेशी पूंजी के प्रकार ○ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ○ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)FDI) ○ भारत में एफडीआई मार्ग • नई एफडीआई नीति ○ एफडीआई के लाभ ○ एफडीआई के नुकसान • भारत में एफडीआई बढ़ाने के सरकारी उपाय • भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नियामक ढांचा • FDI से संबंधित भारत में महत्वपूर्ण सरकारी प्राधिकरण • विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) • भारत में एफपीआई • बहुराष्ट्रीय कंपनियांनिगम / • बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रकार • बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ • बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नुकसान • सार्वजनिक वितरण प्रणाली • निर्यातआयात नीति- ○ भारत की विदेश व्यापार नीति 2015-2020 ○ 2020 में विदेश व्यापार नीति में किए गए परिवर्तन ○ नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 • 15वाँ वित्त आयोग ○ 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें	**127**
15.	**वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तिया** • वैश्विक आर्थिक मुद्दे ○ व्यापार संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध ○ व्यापार संरक्षणवाद के तरीके ○ व्यापार संरक्षणवाद के लाभ ○ व्यापार संरक्षणवाद के नुकसान • अमेरिकाचीन व्यापार युद्ध- ○ खतरा ○ भारत के लिए अवसर	**139**

	• कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी
	  ○ वर्तमान मूल्य वृद्धि के कारण
	  ○ भारत पर प्रभाव
	• दूसरी महामंदी
	  ○ चिंता का विषय
	  ○ वैश्विक प्रभाव
	• विश्व बैंक
	• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)
	• विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)
	  ○ विश्व व्यापार संगठन के निर्माण के कारण
	  ○ विश्व व्यापार संगठन व्यापार के सिद्धांत
	  ○ विश्व व्यापार संगठन-दोहा विकास एजेंडा
	• अन्य वस्तु व्यापार समझौते
	  ○ स्वच्छता और पादप स्वच्छता (SPS) उपाय
	  ○ कृषि पर समझौता (AoA)
	  ○ व्यापार सुविधा समझौता (TFA)
	  ○ सूचना प्रौद्योगिकी समझौता
	  ○ नैरोबी वार्ताएं और भारत
	  ○ ब्यूनस आयर्स सम्मेलन और भारत
	  ○ भारत और विश्व व्यापार संगठन	

16.	**विकासशील, उभरते और विकसित देश**
	• विकासशील देश
	  ○ विकासशील देशों की सामान्य विशेषताएं
	  ○ विकासशील देश और विश्व व्यापार संगठन:
	  ○ विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों को लाभ
	  ○ मुद्दे
	• उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
	  ○ उभरती अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं:
	  ○ उभरते बाजार के लाभ
	  ○ उभरते बाजार के नुकसान:
	• विकसित देश
	  ○ विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएं
		153

1 CHAPTER राष्ट्रीय आय

- **राष्ट्रीय आय:** मूल्यह्रास को समायोजित करने के बाद, एक लेखा वर्ष के दौरान सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
  - यह कारक लागत (FC) पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) है।
  - इसमें कर, मूल्यह्रास और गैर-कारक इनपुट (कच्चा माल) शामिल नहीं है।
- देश की प्रगति के निर्धारण में भी उपयोगी है।
- इसमें निहित हैं: मजदूरी, ब्याज, किराया और उत्पादन के घटकों द्वारा प्राप्त लाभ जैसे: श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमिता।
- **घरेलू आय**: मूल्यह्रास को समायोजित करने के बाद, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
  - यह कारक लागत पर एनडीपी(NDP) है।
- एनएनपी(NNP) और एनडीपी(NDP) दोनों को स्थिर कीमतों (वास्तविक आय) या बाजार मूल्य (नाममात्र आय) पर मापा जा सकता है।
- **राष्ट्रीय आय:** घरेलू आय + एनएफआईए

कुछ महत्वपूर्ण शर्तें	
कारक लागत(FC)	• किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या उपयोग किए गए उत्पादन के सभी कारकों की कुल लागत।
मूल क़ीमत(BP)	• जब किसी सेवा या वस्तु के उत्पादन के कारक लागत में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाए जाने वाले सभी करों को जोड़कर उसमें से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली सभी सब्सिडियों को घटाया जाता है तब प्राप्त मूल्य मूल कीमत कहलाता है। • मूल कीमत(BP)= कारक लागत(FC)+ उत्पादन कर(PT) - उत्पादन सब्सिडी(PS)
बाजार मूल्य(MP)	• जिस कीमत पर कोई वस्तु बाजार में बेची जाती है। इसमें मजदूरी, किराया, ब्याज, इनपुट मूल्य, लाभ और उत्पादन की अन्य लागतें निहित हैं। • सरकार द्वारा लगाए गए कर और सरकार द्वारा प्रदान की गई उत्पादन सब्सिडी भी निहित है। • बाज़ार मूल्य(MP)= मूल कीमत(BP)+ उत्पाद कर(PT) - उत्पाद सब्सिडी(PS) या बाज़ार मूल्य(MP)= कारक लागत(FC)+ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर(NIT)
मूल्यह्रास	• मूल्यह्रास का अर्थ पूंजीगत संपत्ति के मूल्य में समय के अनुसार आने वाली कमी से है। मूल्यह्रास के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे- - सम्पत्ति का पुराना हो जाना (मशीनरी/फर्नीचर) - उसका प्रचलन से बाहर हो जाना - तकनीकी में बदलाव आना / अपग्रेड होना
स्थानान्तरण भुगतान	• एक मौद्रिक भुगतान जिसके लिए कोई वस्तुओं या सेवाओं का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है। • स्थानीय, राज्य और संघीय सरकारों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को धन के पुनर्वितरण के प्रयासों को आमतौर पर हस्तांतरण भुगतान के रूप में संदर्भित किया जाता है।

	• सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी बीमा जैसे हस्तांतरण भुगतान संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय हैं। • स्थानांतरण भुगतान का उपयोग आमतौर पर कॉर्पोरेट, राहत पैकेज और सब्सिडी का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय आय के पहलू

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

- किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
- आर्थिक संकेतक किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- नियमित अवधियों पर अनुमानित (जैसे- त्रैमासिक / वार्षिक)
  - भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है।
- सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उत्पादन क्षेत्र में शामिल हैं-
  - किसी देश की भौगोलिक सीमाएँ जिसमें उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) शामिल हैं। (200 समुद्री मील या 360 किलोमीटर तक)
  - विभिन्न देशों में एक देश का दूतावास
  - वाहन जैसे जहाज, विमान आदि जिस देश में पंजीकृतहोते हैं, वे उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत माने जाते हैं।
- उत्पाद में निहित हैं: देश के घरेलू क्षेत्र में सामान्य निवासियों और अनिवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएँ और सेवाएँ।
  - विदेश से शुद्ध कारक आय (NFIA) शामिल नहीं है।
- केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा गणना की जाती है।
- 'मात्रात्मक अवधारणा' और अर्थव्यवस्था की आंतरिक ताकत को इंगित करता है।
- आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा सदस्य की अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।

जीडीपी = खपत + निवेश + सरकारी खर्च + निर्यात - आयात

सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए तरीके:

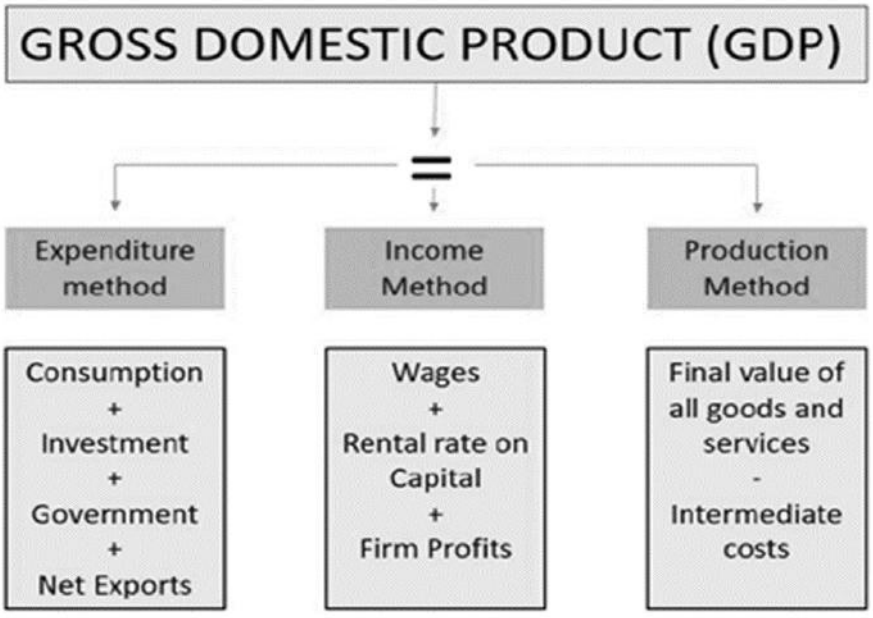

सांकेतिक जीडीपी	वास्तविक जीडीपी
• देश के भीतर उत्पादित कुल वित्तीय व्यवसाय मूल्य। • मुद्रास्फीति के बिना समायोजित। • चालू वर्ष की कीमतों पर। • उच्च मूल्य • एक वर्ष की तिमाहियों की तुलना करता है। **सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद = चालू वर्ष में उत्पादन ✖ चालू वर्ष में मूल्य** • अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रदर्शन को नहीं दर्शाता है।	• जीडीपी मीट्रिक समायोजित : सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन के साथ। • मुद्रास्फीति से समायोजित • नियमित कीमतों पर • कम मूल्य • दो या दो से अधिक वित्तीय वर्ष की तुलना करता है। **वास्तविक जीडीपी = चालू वर्ष में उत्पादन ✖ आधार वर्ष मूल्य** • केवल वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन के आँकड़े सम्मिलित किये जाते हैं।

जीडीपी अपस्फीतिकारक(GDP Deflator)

- उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है।
- मुद्रास्फिति माप संकेतक है जो CPI सूचकांक की तुलना में अधिक व्यापक है।

जीडीपी डिफ्लेटर =सांकेतिक जीडीपी / वास्तविक जीडीपी

जीडीपी विकास दर:

- मापता है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है।
- जीडीपी में लगातार दो वर्षों या तिमाहियों में परिवर्तन को मापता है।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर = 100 x [(जीडीपी चालू वर्ष/तिमाही – जीडीपी पिछला वर्ष/तिमाही)/जीडीपी पिछला वर्ष/तिमाही]

- वास्तविक आर्थिक विकास दर क्रय शक्ति को ध्यान में रखती है और इसमें मुद्रास्फीति-समायोजित होती है।

कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपीएफसी)

- कारक लागत एक वस्तु के उत्पादन की लागत है। इसमें भूमि, श्रम, पूँजी और उत्पादक के मुनाफे की लागत शामिल होती है।

बाजार मूल्य पर जीडीपी (GDPMP)

- बाजार मूल्य में साधन लागत के साथ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। (शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कुल अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच का अंतर)

GDPMP = GDPFC + अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी

सकल मूल्य वर्धित(GVA)

- इसमें GDP की गणना बाज़ार मूल्य पर की जाती है, जिसमें उत्पादन के विभिन्न चरणोंको शामिल किया जाता है।
- इसमें दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं के आधार पर गणना की जाती है।

GVA = GDP + सब्सिडी - कर

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)

- किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर सृजित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल संपत्ति।
- राष्ट्रीय पूंजी परिसंपत्तियों जैसे मशीनरी, घरों और कारों के मूल्यह्रास का मूल्य एनडीपी की गणना के लिए जीडीपी से घटाया जाता है।
- अन्य कारण: परिसंपत्ति का अप्रचलन और पूर्ण विनाश को भी एनडीपी द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद(NDP) =सकल घरेलू उत्पाद(GDP) –मूल्यह्रास.

- **महत्व**
  - अर्थव्यवस्था को मूल्यह्रास के कारण हुए नुकसान की ऐतिहासिक स्थिति को समझना।
  - तुलनात्मक अवधि में उद्योग और व्यापार में मूल्यह्रास की क्षेत्रीय स्थिति को समझना और विश्लेषण करना।
  - आर और डी के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है, जिन्होंने ऐतिहासिक समय अवधि में मूल्यह्रास के स्तर को ठीक करने का प्रयास किया है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

- किसी देश में नागरिकों और उद्यमों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, चाहे वे कहीं भी उत्पादित हों।
- यह विदेशों से अपनी आय के साथ जोड़ा गया देश का सकल घरेलू उत्पाद है।
- 'विदेश से आय' में निम्नलिखित शामिल हैं :
  - व्यापार संतुलन: किसी देश के कुल निर्यात और आयात का वर्ष के अंत में शुद्ध परिणाम।
  - बाहरी ऋणों पर ब्याज: देश द्वारा उधार दिए गए धन पर ब्याज की शेष राशि और उस धन पर ब्याज जो उसने अन्य देशों से उधार लिया है।
    - भारत हमेशा विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक 'शुद्ध ऋणी' रहा है।
  - निजी प्रेषण: विदेशों में काम कर रहे भारतीयों (भारत में) और भारत में काम कर रहे विदेशी नागरिकों (अपने गृह देशों में) द्वारा 'निजी हस्तांतरण' का खाता।

GNP(Y) =उपभोग व्यय (सी) + निवेश (आई) + सरकारी व्यय (जी) + शुद्ध निर्यात (एक्स) + विदेश से शुद्ध आय (Z).

- **Y = C + I + G + X + Z**

- जीएनपी के कारक: उपकरण, मशीनरी, कृषि उत्पादों और करों और कुछ सेवाओं जैसे परामर्श, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी वस्तुओं का निर्माण।
- सेवाओं को वितरित करने की लागत की गणना नहीं की जाती है।
- जब कोई नागरिक दोहरी नागरिकता रखता है तो प्रति व्यक्ति जीएनपी का उपयोग देश-दर-देश के आधार पर जीएनपी की गणना के लिए किया जाता है।
- उस स्थिति में, उनकी आय को प्रत्येक देश के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में दो बार गिना जाता है।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को हटाकर प्राप्त मूल्य NNP कहलाता है।
- यह निर्धारित करता है कि एक देश एक विशिष्ट समय अवधि में कितना उपभोग कर सकता है।

NNP = GNP –मूल्यह्रास
or
NNP = GDP + विदेशों से आय - मूल्यह्रास

- जब किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) गिरता है,

- व्यवसाय उन उद्योगों में स्थानांतरित होने पर विचार करते हैं जिन्हें मंदी-अभेद्य माना जाता है।

निजी आय(PI)	• किसी देश के नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से अर्जित की गई धन राशि। • जैसे रोजगार से प्राप्त धन, निवेश द्वारा भुगतान लाभांश और वितरण, संपत्ति के स्वामित्व से प्राप्त किराया, और उद्यमों से लाभ साझा करना। • अधिकांश मामलों में व्यक्तिगत आय पर कराधान लगाया जाता है। **PI = राष्ट्रीय आय – अविभाजित लाभ– परिवारों द्वारा प्रदत्त शुद्ध ब्याज – कॉर्पोरेट टैक्स + सरकार और फर्मों से परिवारों को भुगतान हस्तांतरण**
व्यक्तिगत प्रयोज्य आय(PDI)	• परिवारों के लिए उपलब्ध आय जिसे वे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं। • करों के भुगतान और अन्य गैर-कर भुगतान के बाद उपलब्ध आय। **PDI = PI – निजी कर भुगतान– गैर-कर भुगतान**
राष्ट्रीय डिस्पोजेबल आय	• संस्थागत क्षेत्रों की सकल (या शुद्ध) प्रयोज्य आय का योग। **सकल (या शुद्ध) एनडीआई = सकल (या शुद्ध) राष्ट्रीय आय (बाजार कीमतों पर)- अनिवासी इकाइयों को देय वर्तमान स्थानान्तरण**

राष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीके

आय विधि	• स्वरोजगार द्वारा सभी उत्पादन कारकों (किराया, वेतन, ब्याज, लाभ) और मिश्रित-आय को जोड़कर अनुमानित। • हम इस प्रक्रिया का उपयोग करके किसी दिए गए वर्ष में किसी देश के सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त सभी शुद्ध आय भुगतान को जोड़ते हैं। • उत्पादन के सभी कारकों से होने वाली शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। ○ उदाहरण: शुद्ध किराया, मजदूरी, ब्याज, और मुनाफा। • हस्तांतरण भुगतान के रूप में प्राप्त आय इसमें शामिल नहीं की जाती। **शुद्ध राष्ट्रीय आय = कर्मचारियों का मुआवजा + मिश्रित परिचालन अधिशेष (W +R +P +I) + शुद्ध आय + विदेश से शुद्ध कारक आय** **जहाँ**, ■ **W** = Wages and salaries ■ **R** = Rental Income ■ **P** = Profit ■ **I** = Mixed Income

उत्पाद/मूल्य वर्धित विधि	• एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश में बाजार कीमतों पर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
	• जीएनपी की गणना करने के लिए,
	  ○ सभी उत्पादक गतिविधियों से डेटा एकत्र किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। इसमे निम्नलिखित शामिल हैं :
	  ▪ कृषि माल,
	  ▪ खनिज, और

	▪ औद्योगिक उत्पादों ▪ परिवहन, बीमा, संचार, वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षकों आदि द्वारा किए गए उत्पादन में योगदान। **राष्ट्रीय आय = जीएनपी - पूंजी की लागत - मूल्यह्रास - अप्रत्यक्ष कर**
व्यय विधि	● राष्ट्रीय आय को व्यय प्रवाह के रूप में मापा जाता है। ● इसमें समाज द्वारा कुल व्यय का योग शामिल है : ○ निजी उपभोग व्यय, ○ शुद्ध घरेलू निवेश, ○ वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी खर्च, और ○ शुद्ध विदेशी निवेश। **राष्ट्रीय आय = राष्ट्रीय उत्पाद = राष्ट्रीय व्यय**

आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति

- **गठन:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) द्वारा।
- **अध्यक्ष**: पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद्
- **कार्य**
  - विश्लेषण और विकास : रोजगार, उद्योग और सेवाओं पर देश का सर्वेक्षण
  - डेटा स्रोतों, संकेतकों और परिभाषाओं के वर्तमान ढ़ांचे को देखना
    - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, समय-समय पर श्रम बल सर्वेक्षण, समय उपयोग सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना और असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों के लिए।
  - 4 स्थायी समितियों श्रम बल सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी, सेवा क्षेत्र, और अनिगमित क्षेत्र की फर्मों को SCES में समाहित किया जाएगा।
  - 108 अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारत में सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रभावित करने में "राजनीतिक भागीदारी" पर चिंता व्यक्त की।
    - सांख्यिकीय संगठनों की "संस्थागत स्वतंत्रता" और अखंडता को बहाल करने की अपील की।

2 CHAPTER लोक वित्त

- विभिन्न सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थानों, नीतियों और उपकरणों के माध्यम से देश के राजस्व, व्यय और ऋण का प्रबंधन।

अवयव

- सार्वजनिक राजस्व
- सरकारी व्यय
- सार्वजनिक ऋण
- राजकोषीय नीति
- वित्तीय जांच
- वित्तीय प्रशासन
- सार्वजनिक उधार।

सब्सिडी

"वस्तुओं की कीमतें कम रखने के लिए राज्य, सार्वजनिक निकाय या अन्य संस्था द्वारा दी गई धनराशि।"

- यह एक अनुदान या वित्तीय सहायता का अन्य रूप है जो उन्हें समर्थन या विकसित करने के उद्देश्य से दिया जाता है।
- कमोडिटी बाजार के माध्यम से उनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे अनुदान वाली वस्तु के सापेक्ष कीमत कम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मांग में वृद्धि होती है।
- वे सरकारी बजट के व्यय पक्ष में होते हैं।
- वे प्रचार के लिए पैसा बढ़ाते हैं जबकि कर इसे कम करते हैं।
- उन्होंने पुनर्वितरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से समाज के सभी सदस्यों के लिए भोजन और पोषण का एक बुनियादी स्तर सुनिश्चित करने के लिए तर्क दिया।

कृषि सब्सिडी की आवश्यकता

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48:** कृषि को आधुनिक तर्ज पर संगठित करने का राज्य का दायित्व।
- एफएओ के अनुसार, 70% भारतीय ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं।
- **सब्सिडी:** आय वितरण और असमानताओं को कम करने का उपकरण (ऑक्सफैम रिपोर्ट 2020- शीर्ष 10% में 72% संपत्ति है)।
- किसानों को कम आमदनी (किसानों की आय गैर-किसानों की आय के 1/3 से कम है)
- कृषि सब्सिडी किसानों के लिए एक पूरक आय के रूप में कार्य करती है, जिसे कृषि में वापस निवेश किया जा सकता है।
- कृषि सब्सिडी बीज, उर्वरक जैसे गुणवत्ता वाले इनपुट तक पहुंच उत्पादकता में वृद्धि किसानों को बेहतर आय।
- कृषि सब्सिडी एक प्रकार से किसानों को व्यवसाय के रूप में खेती जारी रखने के लिए प्रेरित करती है।
- किसानों को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्याओं से बचाना।

सब्सिडी का वर्गीकरण

प्रत्यक्ष अनुदान

- यह अनुदान सीधे किसानों को दी जाती है और आमतौर पर सीधे नकद सब्सिडी के रूप में होती है।

- फलस्वरूप, प्रत्यक्ष अनुदान किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने और ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- अधिकांश औद्योगिक देशों में प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी लोकप्रिय है,
  जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, जबकि भारत उन्हें केवल सीमित रूपों में प्रदान करता है, जैसे कि खाद्य सब्सिडी और एमएसपी-आधारित खरीद।

खाद्य अनुदान

- सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए खाद्य सब्सिडी देती है
  - न्याय वितरित करना, और खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दोहरे उद्देश्य,
  - सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के माध्यम से जरूरतमंदों को न्यूनतम पोषण सहायता प्रदान करना और विभिन्न राज्यों में कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना।
- खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गम मूल्य के बीच का अंतर एफसीआई को वापस कर दिया जाता है,
  - जो गरीबों को गेहूं और चावल बांटते थे और बफर स्टॉक रखते थे।

प्रत्यक्ष सब्सिडी की सीमाएँ

- ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और एटीएम का अभाव है।
- बैंकिंग सेवाएं मुश्किल से आती हैं।
- संभावना है कि किसान गैर-कृषि, गैर-उत्पादक प्रयोजनों के लिए धन खर्च करेंगे।
- आम जनता के हाथ में अधिक धन होने से मुद्रास्फीति हो सकती है।
- इसका असर देश की खाद्य सुरक्षा पर हो सकता है।
- बाजार सुधार और कृषि नवाचार दो प्रमुख चुनौतियां हैं जिनका समाधान किया जाना बाकी है।
- लाभार्थियों की पहचान करने में समस्याएं हैं।

अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान

- ये पैसे के रूप में नहीं बल्कि निम्न रूप में होते हैं :
  - सिंचाई अनुदान
  - बिजली अनुदान
  - उर्वरक अनुदान
  - बीज अनुदान
  - ऋण अनुदान
  - कृषि ऋण माफी,
  - कृषि अनुसंधान, पर्यावरण सहायता में निवेश,
  - कृषक प्रशिक्षण,
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष सब्सिडी का हिस्सा लगभग 2% है।

उदाहरण

बिजली अनुदान	• बिजली के उपयोग और बिजली पैदा करने की वास्तविक लागत के लिए किसान द्वारा भुगतान की गई कीमत के अंतर के बराबर सब्सिडी।
उर्वरक अनुदान	• सतत कृषि विकास और संतुलित पोषक अनुप्रयोग के लिए किसान को अनुदान प्रदान करना। • उर्वरक सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2018-19 में बढ़कर लगभग 70,000 करोड़ (यूरिया के लिए लगभग

	45,000 करोड़) हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 65,000 करोड़ थी।

ऋण अनुदान	• गरीब किसान नकदी की तंगी से जूझ रहे हैं और ऋण बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऋण के लिए आवश्यक जमानत की कमी है।
	• उत्पादन संचालन जारी रखने के लिए, वे स्थानीय साहूकारों के पास जाते हैं।
	• **क्रेडिट सब्सिडी:** किसान द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज और क्रेडिट देने की वास्तविक लागत के बीच अंतर।
	• सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ कर दिया है।
	  ○ लेकिन 30-40% ग्रामीण ऋण व्यवस्था से बाहर हो रहा है,
	  ○ जैसे किसान 3-4% ब्याज पर कर्ज लेते हैं और फिर सावधि जमा करते हैं।

आधारभूत संरचना अनुदान	• **व्यक्तिगत प्रयास:** बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लंबी अवधि की अवधि के कारण इस तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण व्यवहार्य नहीं है, इसलिए सरकार ऐसी लागतों का ख्याल रखती है।
	• **महत्व:** उत्पादन और बिक्री संचालन करने के लिए
	  ○ परिवहन सुविधाएं।
	  ○ भंडारण सुविधाएं।
	  ○ शक्ति।
	  ○ बाजार की जानकारी।

कृषि सब्सिडी के लाभ और मुद्दे

कृषि अनुदान के लाभ	• छोटे और सीमांत किसानों को सक्षम बनाना - इनपुट की स्थिर आपूर्ति बनाए रखना और कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करना। • अनुदान किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाती है।
कृषि सब्सिडी के मुद्दे	• **खाद्य सब्सिडी:** बजट 2018-19 में 1.70 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि कृषि निवेश केवल 3,000-4,000 करोड़ रुपये के आसपास था, इसलिए खाद्य सब्सिडी को कृषि को सहायता देने के बजाय बेकार माना जाता था। • सब्सिडी वाली कृषि के कारण: हरित क्रांति क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा) में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से असंतुलित एनपीके अनुपात, लवणता में वृद्धि और मिट्टी की उर्वरता में कमी आई। • **भारत में किसान :** सरकार द्वारा अनुदानित फसलों (गेहूं, चावल, चीनी, आदि) के लिए अधिक भूमि और पानी समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। • जिसके परिणामस्वरूप कम उत्पादकता और अन्य चीजों (फल, सब्जियां, आदि) के लिए उच्च लागत होती है। • **सब्सिडी:** विकास खर्च की कीमत पर भुगतान, जिसके परिणामस्वरूप एक सतत राजकोषीय घाटा होता है। • सब्सिडी भी फसल पैटर्न को कम करती है। • उर्वरकों के लिए सब्सिडी मुख्य रूप से उर्वरक उत्पादकों और बड़े खेतों की मदद करती है। • सब्सिडी सुधार के लिए प्रोत्साहन को कम करती है, अक्षमता को बढ़ावा देती है।

संवितरण के विभिन्न तरीके

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण	• **पहल:** जनवरी, 2013 में सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार के लक्ष्य के साथ। • **उद्देश्य:** वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाभार्थियों को सूचना और भुगतान के हस्तांतरण को आसान और तेज बनाना। • **योजनाएँ :** DBT की 317 विभिन्न योजनाएँ हैं। **कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ** • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन • सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन - एनएमएसए-वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना • पीएम किसान • स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण • अटल पेंशन योजना • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना • आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) • दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना • DAY-एनआरएलएम • राष्ट्रीय आयुष मिशन - आयुष सेवाओं के तहत दवाएं
आय समर्थन	**प्रधानमंत्री-किसान** • प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) • पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना। • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित। • सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में सीधे 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष सीधे जमा करने का प्रावधान है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो। • **उद्देश्य:** छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार की गारंटी के लिए विभिन्न इनपुट प्राप्त करने में, जो प्रत्येक फसल चक्र के अंत में अपेक्षित कृषि आय के आनुपातिक हैं। • लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। **सार्वभौमिक मूल आय** • यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो एक निश्चित राशि प्रदान करता है एक भौगोलिक क्षेत्र (एक देश या राज्य) के सभी लोगों के लिए, उनकी आय, संसाधन या नौकरी की स्थिति की परवाह किए बिना। • **UBI का प्रमुख लक्ष्य :** नागरिक समानता में वृद्धि करते हुए गरीबी को रोकना या कम करना। • **प्राथमिक धारणा :** सभी नागरिक, चाहे उनकी जन्म परिस्थिति कुछ भी हो, एक अच्छी आय के हकदार हैं।